participation of people at all levels;

(vii) Empowerment of women and socially disadvantaged groups such as Scheduled Castes, Tribes and Other Backward Classes and Minorities as agents of socio-economic change and devleopment;

(viii) Promoting and developing people's participatory institutions like Panchayati Raj institutions, cooperatives and self-help groups;

(ix) Strengthening efforts to build self-reliance.

The above objectives, which seek to achieve growth with equity", need to be seen in the context of four important dimensions of State Policy. These are; (a) quality of life of the citizens; (b) generation of productive employment; (c) regional balance; and (d) self-reliance.

(c) and (d) A sustained and long lasting solution to the problem of poverty depends on the creation of adequate employment opportunities through a broad based programme if development and economic growth. This is of particular importance since the labour time unemployment rate for male workers has gone up in a significant manner. The very poor are heavily dependent on the slender work opportunities available to them in terms of labour days, and if this comes down, the consequances are very severe. A National employment Assurance Plan has also been introduced.

At a conference of Chief Ministers held in July, 1996, it was decided to implement a programme for the achievement of total coverage of seven Basic Minimum Services in a time bound manner. It was agreed to raise the outlays of these programmes by 15% in spite of stringent fiscal situation. The Ninth Five Year Plan will continue this commitment in real terms through each of the five years. While the objectives of this programme have been decided through the process of mutual consultation, the States have been given full opportunity to decide on the phasing of the target for each specific sector. The achievement of these targets will be jointly monitored by the State and the Central Governments. This approach is an ideal blend of national commitments with local initiatives.

Clearance to Sanitation and Drinking Water Projects of Uttar Pradesh, Harayana and Punjab

2003. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of sanitation and drinking water projects of Haryana, Uttar Pradesh and Punjab pending with Government for clearance and since when;

(b) the reasons for their pendancy; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE FOR PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) No sanitation and drinking water project of Haryana, Uttar Pradesh and Punjab is pending with the Planning Commission for clearance.

(b) and (c) Question does not arise.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को रोजगार

2004. श्री शिव चरण सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं, योजनाओं इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान इन परियोजनाओं हेतु वार्षिक रूप से आवंटित की गई धनराशि का परियोजना/योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में परियोजना-वार उपलब्धियां क्या-क्या रहीं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी को मिलते हैं ये लाभ सभी राज्यों को भी मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो पूरक रोजगार उपलब्ध कराते हैं: ये हैं: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम; जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम। जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित कराने हेतु इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विशेष सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। आई आर डी पी के अन्तर्गत यह निहित है कि लाभग्रहियों के तहत आने वालों में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों। जे आर वाई तथा ई ए एस के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोग लक्षित वर्ग में आते हैं जिसमे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। शहरी विकास क्षेत्र में दो शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीमें चल रही हैं। ये हैं: नेहरु रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री की रोजगार योजना केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही ताकि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। पी एम आर वाई के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभग्रहियों के लिए आरक्षण कुल का 22.5 प्रतिशत रखा गया है।

1994—97 के दौरान प्रमुख स्कीमों के तहत राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रू०)

	आई आर डी पी		वे आर वाई			
	राजस्थान	मध्य प्रदेश	असम	राजस्थान	मध्य प्रदेश	असम
1994-95 में						
उपयोग में लाया गया	43.93	105.73	27.47	188.36	495.83	89.21
आवंटन	46.27	102.77	31.06	199.09	505.03	103.87
1995-96						
उपयोग में लाया गया	43.80	105.65	27.44	208.25	511.19	108.20
आवंटन	47.30	113.06	27.38	184.04	423.77	95.83
1996-97						
उपयोग में लाया गया	43.88	105.65	27.44	91.46	220.15	57.16
आवंटन	12.80	43.27	7.03	32.86	109.43	21.06
(नवम्बर, 1996 तक)						

Allocations Under Employment Generation Schemes in Kerala

2005. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number and details of centrally sponsored employment generation schemes being run in the ocuntry;

(b) the amount allotted to Kerla during 1995-96 and 1996-97 under each scheme; and

(c) the amount, out of the above, utilised so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTER OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINER K. ALAGH): (a) to (c) The major poverty alleviation